Tsunami Evaluation Coalition:

The role of needs assessment in the Tsunami response

सूनामी प्रतिक्रिया में आवश्यकताओ के निर्धारण

कार्यकारी निष्पादन

26, दिसम्बर, 2004 को सूनामी ने हिन्द महासागर को आक्रांत कर दिया । 4 प्रभावित देशों में 225000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई अथवा अभी भी लापता हैं । कुल मिलाकर एक अनुमानतः 20 लाख लोग परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से इससे प्रभावित हुए

यह मूल्यांकन उन पांच विषयक मूल्यांकनों में से एक है जिसे सूनामी की अंतर्राष्ट्रीय मानवीय प्रतिक्रिया पर 'सूनामी मूल्यांकन दल' (टीईसी) द्वारा किया गया । इस क्रम में अन्य चार हैं- सहायोग; स्थानीय व राष्ट्रीय क्षमताओं पर प्रतिक्रिया का पहलू; सहायता पुनर्वास व विकास के बीच सहलग्नता; एवं सूनामी के निधिकरण की प्रतिक्रिया । यह रिपोर्ट सूनामी के बाद प्रथम तीन माह में निर्धारण की प्र्याप्तता, औचित्य व प्रभाविकता की आवश्यकता का मूल्यांकन करती है । यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और संस्थागत दानकर्ताओं व अंततः प्रभावित जनसंख्या की प्रतिक्रिया पर निर्धारण के पहलू को केंद्रित करता है ।

50 एजेंसियों के 300 से अधिक कर्मचारियों अथवा कार्यकर्ताओं ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड व 7 दानकर्ता देशों ने इस अध्ययन हेतु साक्षात्कार किया । सूनामी के बाद पहले माह में तैयार की गई लगभग 200 रिपोर्टों का राष्ट्रीय परामर्शदाताओं व अनुसंधान सहयोगियों ने पुनरावलोकन किया । क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रभावित व्यक्तियों से 135 असंरचनात्मक साक्षात्कार किए गए ।

कुछ भिन्न प्रकार के निर्धारण हैं जिनकी तुलना सहज नहीं है ।

- अल्प अवधि, तीव्र परिवर्तन व तत्प्रभावी मानवीय आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, भोजन व आश्रय का निर्धारण की विषमता में विनाश व हानि (रिकवरी आवश्यकताओं का आर्थिक मूल्यांकन) के साथ निर्धारण ।

-पार क्षेत्रीय/खण्डीये निर्धारण बनाम अत्यधिक विशिष्ट विषयक अथवा क्षेत्रीय सर्वेक्षण ।

-स्थिति विश्लेषण को प्रेरित करते वर्णात्मक संकलन की तुलना में औपचारिक, संरचनात्मक व प्रायः वैज्ञानिक निर्धारण ।

-उपलब्ध अथवा सामान्य, आम प्रयोग के अभीष्ट निर्धारण उन निर्धारणों के विरूद्ध थे जो बिना बंटे रह गए एवं उन्हें अंतः एजेंसियों के लिए रख लिया गया ।

इस रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रभाव से अभिप्रेरित होकर लिए गए निर्णयों के निर्धारणों का पुनरावलोकन है । अधिकांश निष्कर्ष विशेष रूप से संयुक्त राष्ट अथवा इसकी अंतः एजेंसियों की रिपोर्ट पर केंद्रित हैं, क्योंकि रेडक्रॉस से संबंधित औपचारिक जानकारी मूल्यांकनकर्ताओं के पास उपलब्ध नहीं थी । स्वास्थ्य, जल व साफ-सफाई, भोजन व पोषण जीवन की रिकवरी/सुधार(विशेष रूप से मत्स्यकरण में) तथा आश्रय पर चयनित निर्धारण का बड़ी गहराई से पुनरावलोकन किया गया है जो रिपोर्ट के संलग्नकों में दिया है ।

सामान्य निष्कर्ष

आवश्यकता निर्धारण का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित आधार का प्रयोग किया गया है-सामयिकता, संरक्षण, वैधता, समन्वय व निरन्तरता । आवश्यकताओं के निर्धारण की प्रभावपूर्णता का पुनरावलोकन मूल्य संवर्द्धन, अपील व निर्णयों पर प्रसार व प्रभाव की सीमा के अंतर्गत किया है ।

मानवीय आवश्यकता निर्धारण की सामयिकता का निर्धारण-योग्य कार्मिकों को पहचानने की एजेंसी की क्षमता, तार्किक साधनों को गति प्रदान करना व निर्णय करने वालों को आवश्यकता की महत्ता की सूचना देना, द्वारा किया गया था । बहुत से कार्यकर्ता इंडोनेशिया व श्रीलंका के प्रभावित इलाकों की ओर दौड़े जिससे प्रभावित जनसंख्या की अतिआवश्यक आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके । जनसंपर्क माध्यम-न तो संयुक्त राष्ट्र अथवा अन्य मानवीय संकाय, तत्प्रभावी आवश्यकताओं का त्वरित व विश्वासोत्पाद व्यापक औपचारिक निर्धारण उपलब्ध करने के योग्य पाए गए । यदि संयुक्त राष्ट्र व रेडक्रॉस के निर्धारणों की सामयिकता आपत्तिजनक थी, तो एजेंसियों ने अपनी स्वयं की योजनाओं के निर्धारण रूपरेखा बनाकर व समय से किया, क्योंकि निर्णय उन निर्धारणों के परिणाम पर आश्रित थे ।

रिकवरी के आवश्यकता निर्धारण, विशेष रूप से विनाश व हानि को, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों(आईएफआई) ने किया, जिसकी असाधारण रूप से पहले ही इस बात से तुलना कर ली थी कि अन्य आपदाओं से क्या प्राप्त किया था । इंडोनेशिया में रिकवरी निर्धारण को सूनामी के दिन से ही आरंभ कर दिया था ।

भौगोलिक क्षेत्र व पहलू की महत्ता देते हुए आवश्यकताओं की व्यापक उपलब्धता कठिन है । हालांकि, कोई पार क्षेत्रीय मानवीय आवश्यकता का निर्धारण किसी एक देश में भी सारे प्रभावित क्षेत्र को समाहित नहीं कर सकता । मानवीय विषयक सर्वेक्षण(पोषण, भोजन व रोग निगरानी पर) और विशिष्ट जीवनयापन निर्धारण(उदाहरणार्थ भोजन व आश्रय) में विस्तृत भौगोलिक व्याख्या की गई, लेकिन आर्थिक बृहत निर्धारण में विनाश व हानि की बेहतर व्याख्या की गई थी ।

बहुत सी आवश्यकताओं निर्धारणों के पुनरावलोकन की वैधता का निर्णय लेने के लिए इसकी कार्यप्रणाली के बारे में थोड़ी ही सूचना उपलब्ध है । कुछ कमियां सुस्पष्ट हैं, फिर भी त्वरित निर्धारण के लिए अद्वितीय आरूप की कमी, कौन प्रभावित है तथा कौन सहायता के योग्य है, की परिवर्ती परिभाषा तथा स्थानीय पक्षमार्जन क्षमता का अनादर जैसे किसी भी आवश्यकता को राष्ट्रीय व स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं पूरा किया जाएगा । मूल्यांकन के समय (सितंबर 2005) लक्षित जनसंख्या व संभावित लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या के बीच भ्रम भी मुख्य मुद्दा था ।

शक्तिशाली सरकार के द्वारा थाईलैंड, भारत व मालद्वीप जैसे देशों में बेहतर समन्वय था । श्रीलंका में जहां दानकर्ताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों व मात्र एक एजेंसी ने एक बल में हिस्सा लिया और इंडोनेशिया में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयर कैरियर की अंतःएजेंसी के स्वास्थ्य निर्धारण के मामले में प्रारंभिक आवश्यकता निर्धारण के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के प्रति गंभीर प्रयास ध्यान में आए ।

मानवीय आवश्यकताएं बड़ी तीव्रता से परिवर्तित हुईं क्योंकि अधिक सहायता कि आने से प्रभावित कुटुम्बों की प्राथमिकता रिकवरी की ओर खिसक गई । कुछ थोड़े से सीमित क्षेत्रों (उदाहरणार्थ सक्रामक रोग का जोखिम, व मौके पर भोजन की उपलब्धता) को छोड़कर मानवीय समुदाय निरंतरता के आधार पर उन अल्पकालीन आवश्यकताओं के मूल्यांकन का प्रबोधन करने योग्य नहीं था । मानवीय आवश्यकता निर्धारण तीव्रता से अप्रचलित हो गया । कुटुम्ब के जीवनयापन की आवश्यकताओं(उदाहरणस्वरूप नावों व आवास के लिए) में कम तेजी से परिवर्तन आया और यंत्र रचना ने उतरोत्तर वास्तविक समय में उन आवश्यकताओं का प्रबोधन किया ।

यदि आवश्यकता निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के निर्देशन में प्रभावी थे तो उपरोक्त विशिष्टताएं महत्वहीन होंगी । हालांकि आंतरिक निर्धारण(वे जिन्हें एजेंसियों ने स्वयं की कार्यप्रणाली के लिए किया) प्रभावी हो सकते हैं, अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के प्रयोग के अभीष्ट निर्धारण उतने नहीं । धीमी गति से चलने वाले मानवीय निर्धारणों ने प्रारंभिक/आद्य मानवीय प्रतिक्रिया को संचालित नहीं किया था । कर्मठता की खोज में उपलब्ध विशाल राशियों के कोष संचालित बल था ।

उन मानवीय निर्धारणों की मुख्य कमजोरी संवर्द्धन मूल्य का बोध न होना था । अन्य कारकों के रूप में इसमें विश्लेषण की कमी, प्राथमिकताएं जैसी होनी चाहिए थीं, उनके व्यापक चित्रण के संकलन में कमी, आंतरिक रिपोर्ट के प्रसार में बाधा डालने वाला 'प्रतियोगी संवेदनशील' स्वरूप और दानकर्ताओं(जनता व सरकार) की ओर से निधिकरण को तुरन्त प्रयोग करने का दबाव ।संक्षेप में, जनसंपर्क माध्यम प्रधान लगता है, यदि न केवल प्रभावित देशों के बाहर के वैयक्तिक अथवा संस्थागत निर्णय लेने वालों के लिए आवश्यकताओं का प्रभावी स्रोत । संयुक्त राष्ट्र अथवा निर्धारण व समन्वय दल (यूएनडीएसी) अथवा क्षेत्र निर्धारण व समन्वय टीम (एफएसीटी) जो रेडक्रॉस प्रणाली में यूएनडीएसी के समकक्ष है, की रिपोर्ट अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में प्रभाव छोड़ने में बुरी तरह असफल रहीं ।

परिणामस्वरूप सूनामी से प्रभावित लोगों की वास्तविक महत्वाकांक्षाओं के साथ किया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का मिलान खराब था जिन्होंने महसूस किया कि बिना उनकी परामर्श के उनका अतिमूल्यांकन कर दिया गया-जैसा कि इस मूल्यांकन में कुटुम्बों के साक्षात्कार के अप्रतिनिधित्व नमूने एवं स्थानीय क्षमता पर किए गए टीईसी मूल्यांकन के व्यापक सर्वेक्षण द्वारा

दर्शाया गया है । इसमें एक उल्लेखनीय अपवाद रेडक्रॉस व एनजीओ द्वारा कार्यान्वित नकदी पर आधारित कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभावित परिवारों को शक्तिवान बना दिया था ।

निष्कर्ष

मूल्यांकनकर्ताओं ने जो कमियां नोट कीं उनमें से समस्त नहीं तो अधिकांशतः भूतकाल में केंद्रीय अमरीका में ह्यूरीकेन मिच से लेकर गुजरात(भारत) व बाम(ईरान) में आए भूकम्प से अचानक आई प्राकृतिक आपदाओं में पहले घट चुकीं थीं । निःसंदेह विलक्षण हालात थे जिन्होंने सूनामी प्रतिक्रिया को प्रभावित किया : तथ्य कि दक्षिण पूर्व एशिया महत्वपूर्ण भूराजनैतिक व आर्थिक परिवर्तन का क्षेत्र है, ऐसिह के नागरिक दंगे विश्व के बड़े मुस्लिम देशों में भी घटित हुए, पीड़ितों में बहुत से पर्यटकों की उपस्थिति और बहुत से पाश्चात्य विश्व में अवकाश के साथ समय अनुरूपता । फिर भी, सर्वोपरि रूप से माध्यम आच्छादन की प्रबलता व जनता की हद से ज्यादा उदारता इस आपदा को इसकी भौगोलिक पैमाने, तार्किक दबाव अथवा सुरक्षा व राजनैतिक वातावरण से अधिक पृथक करते हैं ।

उदार निधिकरण ने न केवल अत्यधिक रूप से फैले मानवीय उद्योग की अवशोषण क्षमता को बढ़ाया, और इसके प्रथागत बहाने को तंत्र की कमी का भाग बनने से वंचित किया, अपितु नए कार्यकर्ताओं के प्रचूर प्रसरण को अपर्याप्त अनुभव में परिणत किया (और इसलिए योग्यता) साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में ऐसी गतिविधियों के प्रति साहस स्थापित किया जो उनकी विशेषज्ञता के सामान्य क्षेत्र से बाहर थीं । अंततः, निर्धारण करने, समन्वय करने व कुछ सामूहिक निर्धारणों के परिणाम को लागू करने में अधिक निधिकरण अनुत्साहन था ।

यह मूल्यांकन जीवनयापन रिकवरी आवश्यकता निर्धारण के संपादन से अल्पकालीन मानवीय आवश्यकताओं को आच्छादित करने वाले निर्धारणों से तुलना करता है । बाद के

सप्ताहों में किए गए निर्धारणों की तुलना में पहले कुछ दिनों में किए गए निर्धारण कठिन आपत्ति प्रस्तुत करते हैं । मानवीय आवश्यकताओं के अल्प जीवन में निर्धारण को, जैसे ही ये पूरे हुए, लगभग अप्रचलित कर दिया । अंततः थोड़े (और प्रायः अधिक अनुभवी) अभिकर्ता रिकवरी पर केंद्रित थे, जबकि अधिकांश अनुभवशून्य कार्यकर्ताओं ने अधिक तत्प्रभावी व दृष्टिगोचर मानवीय गतिविधियों को संगठित किया । मानवीय एजेंसियों को आईएफआई द्वारा अपनाई गई विचारधारा से बहुत कुछ सीखना है : सभी साझेदारों में कालोचीत सहयोग (राष्ट्रीय सरकार सर्वोपरि), विशेषज्ञता का महत्वपूर्ण प्रवाह व स्पष्टता तथा विश्लेषकों के दल का सूचना के विभिन्न स्रोतों का मेल-मिलाप व संकलन करने के लिए प्रयोग करना ।

निर्धारण विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के बीच अंतर प्रकट करने व प्राथमिकता दर्शाने वाले होने चाहिए : जो पूर्ववर्ती स्थिति से परिणित हैं, जो वास्तव में जीवन संतर्जक हों जो अच्छी प्रकार स्थानीय रूप से पूर्ण हों व अंततः निर्धारण करने वाली एजेंसियों के बजाय 'हिताधिकारियों' को स्वयं प्राथमिकता का अनुभव करएं । प्रायः व अधिक रूप से स्थिति की समीक्षा व निर्धारण, सक्रिय हिताधिकारियों से अधिक निर्धारण एजेंसियों के हित अथवा आदेशपत्र की पूर्ति करता है ।

यह निर्धारण बड़ी संख्या में ऐसे संगठनों व दलों द्वारा किया गया जिनका जन्म व समर्पण सूचनाओं की उत्पन्नता अथवा प्रबंधन के लिए था । इस मूल्यांकन के पुनरावलोकन में यूएनडीएसी, मानवीय सूचना केंद्र(एचआईसी), एफएसीटी, क्षेत्रीय व सामूहिक आधार की एजेंसियां व अन्य बहुत से द्विपक्षीय दल शामिल थे ।

-यूएनडीएसी को महत्वपूर्ण मजबूती की आवश्यकता है । इंडोनेशिया में अपूर्ण आवश्यकताओं के चित्रण की नई व उपयोगी सूचनाओं के निर्धारण व विश्लेषण से अधिक

बहुत थोड़े मानव संसाधन बड़ी संख्या में साझेदारों को समन्वित पर अधिक केंद्रित हैं । यह अत्यावश्यक है कि यूएनडीएसी की दानकर्ता पर आधारित समस्त अवधारणा पर पुनर्विचार किया जाए ।

-प्राकृतिक आपदाओं के बाद की गणना में एचआईसी एक अच्छी पहल है । इसे संयुक्त राष्ट्र के पुरालेख के कार्य के बजाय और अधिक विश्लेषणात्मक रूप से विस्तृत प्रबंधन क्षमता के ज्ञान का हिस्सा बन जाना चाहिए । एचआईसी अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज अप्रचलित थे एवं प्रायः उनका कोई व्यावहारिक संबंध नहीं था ।

-अनौपचारिक तंत्र/नेटवर्क से प्राप्त साक्षात्कार व दस्तावेज दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि रेडक्रॉस के आंदोलन एफएसीटी का रेडक्रॉस समितियों के भाग लेने संबंधी आपातकालीन प्रतिक्रिया टुकड़ियों(ईआरयू) को भेजने के निर्णय व यूनएनडीएसी पर सरकारी व गैर-सरकारी हस्तक्षेप का कोई अधिक प्रभाव नहीं था । रिकवरी निर्धारण दल(आरएटी) की रिपोर्ट ने रेडक्रॉस आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया था । प्रभावित परिवारों की प्राथमिकताओं के प्रति रिकवरी प्रतिक्रिया को निर्देशित करने वाले उनके प्रभाव का निश्चित रूप से पता नहीं चल सका ।

-यूनएन एजेंसियों द्वारा निर्देशित खण्ड (अथवा ओसीएचए की नई पारिभाषिक शब्दावली में समूह) अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में प्रतिक्रिया को सूचित व निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार है । सहायता परियोजनाओं के सीधे निष्पादन ने कुछ एजेंसियों को इस प्राथमिक जिम्मेदारी से वंचित कर दिया । तकनीकी प्राथमिकताओं (आवश्यकता निर्धारण द्वारा स्थानीय रूप से पता लगाई गईं) व नीति स्तर पर (मुख्यालय में) अपनाई गई प्राथमिकताओं के बीच प्रतिवाद ने कुछ क्षेत्रों में एजेंसियों की विश्वसनीयता को प्रभावित किया ।

-सूनामी के बाद की गणना में तीन अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई : आईएफआई-जिसने विगत आपदाओं के समय की अपेक्षा अच्छे समन्वय के साथ पहले ही कार्यवाही कर दी थी, विदेशी सैना, यद्यपि उसका हस्तक्षेप अधिक मंहगा था, और निश्चित रूप से जनसंपर्क माध्यम जिसने पश्चिमी विश्व में लोक व शासकीय स्तर पर अत्यधिक शीर्ष रणनीति वाले निर्णयों को अप्रत्यक्ष रूप से (व तर्कसाध्य निर्धारण) प्रभावित किया । बाद के दो कार्यकर्ताओं के साथ मानवीय संगठनों की अंतःक्रिया बड़े पैमाने पर अप्रभावित थी ।

-आवश्यकता निर्धारण का एक स्रोत नियमित रूप से नजरअंदाज था : राष्ट्रीय व जिला प्राधिकरण । सभी अंतर्राष्ट्रीय निर्धारणों ने स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों पर भारी विश्वास किया था । राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से इंडोनेशिया में, इन अपरिपक्व आंकड़ों के वैधीकरण, संग्रहण व प्रसार में कमजोरी थी । एक सहज बाह्य प्रतिष्ठापना/निवेश को राष्ट्रीय क्षमता बनने में व आवश्यकताओं का समेकित चित्रण उपलब्ध कराने के लिए काफी लम्बा सफर तय करना पड़ेगा - वह 'बड़ा चित्रण' है, बहुत से दानकर्ताओं व निर्णय करने वालों के विचार में इसका समस्यत प्रतिक्रिया से छूटना ।

अनेक सरकारी एजेंसियों व एनजीओ ने प्रभावित जनसंख्या के उपसमूहों की जनगणना की । श्रीलंका में अधिकांश प्रभावित कुटुम्बों के आंकड़े संभवतः विभिन्न स्वतंत्र आंकड़ों में पंजीकृत हैं । कुछ पंजियां पार-क्षेत्रीय हैं, लेकिन वे एक विशिष्ट एनजीओ अथवा रेडक्रॉस सोसायटी के सेवार्थीवृंद तक ही सीमित हैं, इसके अलावा अन्य विषयक हैं परन्तु वे राष्ट्रव्यापक हैं (उदाहरणार्थ कृषि, मत्स्य, कल्याण अथवा आवासन पर) । आम केंद्रीयकृत आंकड़े संभव होंगे तथा वे ज्यादा प्रभावी होंगे ।

कुल मिलाकर, सूनामी पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय प्रतिक्रिया अपर्याप्त प्रमाण पर आधारित थी । आवश्यकताओं के निर्धारण में दुर्बलता के बावजूद, फिर भी, तर्कसाध्य प्रतिक्रिया प्रभावी थी । प्रति उत्तरजीवी के लिए नियत विशाल निधि भी राशि(लगभग 8000 यूएस डॉलर) दी गई, फिर भी प्रभावितकता आशा से बहुत कम थी । ये प्रभावी नहीं थी । जिन क्षेत्रों अथवा खण्डों में अधिक प्रत्यक्षता प्रदान की गई थी वहां की प्रतिक्रिया प्रायः अधिक थी । कुछ खण्डों के दस्तावेजों के अनुसार समस्या केवल तकनीकी नहीं थी, अपितु राजनैतिक भी थी । सहायता के स्वयं सेवा के ढंगों को हतोत्साहित करने के लिए निर्धारण का संयोजन करने वाली एजेंसिया प्रायः अपने निष्कर्षों का प्रयोग करने की अनिच्छुक थीं । इस विचार ने अत्यधिक मौलिक प्रश्न खड़े किए : यदि शीर्ष निर्णय करने के लिए ज्यादातर परिणाम अप्रसांगिक हैं तो आद्य में निवेश क्यों, औपचारिक मानवीय निर्धारण क्यों ?

अनुशंसाएं

इस मूल्यांकन से निम्न 17 अनुशंसाएं निकलती हैं और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता निर्धारण में सुधार के लिए निम्न उद्देश्यों की दिशा में कुछ कदम सुझाते हैं :

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आवश्यकता निर्धारण में अधिक व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए (अनुशंसा 1-5)
- प्रभावित जनसंख्या को निर्णय करने की सामर्थ्य का पुनः स्थानांतरण जो बाह्य एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले विषयक निर्धारणों की आवश्यकता को कम करेगा (अनुशंसा 6)

- बहुत से वर्तमान दोहरे अथवा प्रतियोगी निर्धारण तंत्र को सरल व कारगर बनाने से निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार होगा (अनुशंसा 7-10)
- जनसंपर्क माध्यम को अपनी निर्णायक भूमिका चालू रखनी पड़ेगी (अनुशंसा 11)
- निर्धारण दलों की तेजी व प्रभाविकता को गतिवान बनाने के लिए नई वित्तीय व प्रशासनिक व्यवस्थाएं अनिवार्य हैं (अनुशंसा 12 व 13)
- अभिवृति में परिवर्तन की आवश्यकता है-विशाल विश्व के 'अनियमित उद्योग' में गुणवत्ता नियंत्रण व जबावदेही लाना चाहिए (अनुशंसा 14-16)
- समस्त प्रभावित व्यक्तियों व कुटुम्बों के पंजीकरण के आंकड़े केंद्रीयकृत होने चाहिए, जिसमें उनकी परिस्थिति व आवश्यकताओं का विवरण शामिल हो (अनुशंसा 17)

1 संयुक्त राष्ट्र व रेडक्रॉस को या तो त्वरित मानवीय आवश्यकता निर्धारण में बृहत निवेश करना चाहिए या यह बहाना बनाना बन्द करना चाहिए कि निर्धारण निर्णय लेने में प्रभाव डालते हैं ।

2 दानकर्ताओं व एजेंसियों को जीवनयापन की रिकवरी हेतु पहले से ही उच्च गुणवत्ता वाले आवश्यकताओं के निर्धारण में निवेश करना चालू रखना चाहिए ।

3 सभी को राष्ट्रीय निर्धारण क्षमता (तैयारी) को बनाने में निवेश करना चाहिए ।

4 भावी निर्धारण राष्ट्रीय प्राधिकरणों के साथ मिलकर करने चाहिए और किसी भी भावी आपदा से पूर्व इस विषय पर औपचारिक समझौता होना चाहिए ।

5 राष्ट्रीय सरकार के साथ प्रारंभिक त्वरित निर्धारण को दूरस्थ संवेदन (उपाश्रित कल्पनाशक्ति) का बड़ा प्रयोग बनना चाहिए ।

6 जब संभव हो नकदी पर आधारित प्रतिक्रिया को अपनाना चाहिए ।

7 संयुक्त राष्ट्र व रेडक्रॉस को संयुक्त बल बनकर आवश्यकता के त्वरित प्रारंभिक निर्धारण में सरकार का समर्थन करना चाहिए ।

8 संयुक्त राष्ट्र को सभी निर्धारण समर्थन घटकों की प्रतिक्रिया को(यूएनडीएसी, एचआईसी, यूएनजेएलसी) एक ज्ञान प्रबंधन कार्यक्रम में एकीकरण करना चाहिए । समन्वय व निर्धारण के लिए मानव व सामग्री संसाधनों को स्पष्ट रूप से पृथक होना चाहिए ।

9 ओसीएचए को आंकड़ों के विश्लेषण में अपनी क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए एवं आवश्यकताओं व अंतरों का व्यापक समेकित व निरंतर चित्रण उपलब्ध कराना चाहिए ।

10 विशिष्ट क्षेत्रों के नेतृत्व वाली एजेंसियों को अपने प्राथमिक निर्धारण एवं मानवीय गतिविधियों के समन्वय व सीधे क्रियान्वयन से विचलित नहीं होना चाहिए ।

11 त्वरित निर्धारण दलों में जनसंपर्क माध्यम के प्रतिनिधियों की अंतःस्थापना पर अधिक गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

12 निधिकरण निश्चित होना चाहिए व त्वरित निर्धारण हेतु नियमित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए ।

13 तत्प्रभावी मानव संसाधनों व तार्किक समर्थन की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धि व भर्ती की कार्यविधि में सुधार लाना चाहिए । यदि यह संभव नहीं है तो बाह्य स्रोत पर विचार करना चाहिए ।

14 तत्प्रभावी आपातकाल से थोड़ा पहले दानकर्ताओं को आवश्यकता के विकास के प्रबोधन हेतु ठोस निर्धारण व स्पष्ट योजना की शर्त के आधार पर निधिकरण करना चाहिए ।

15 संयुक्त राष्ट्र को प्रभावित व्यक्तियों व उनकी आवश्यकताओं की संख्या के अनुमान की विश्वसनीयता में सुधार करना चाहिए । सहायता के अनुपयुक्त प्रकार को अग्रसक्रियता से हतोत्साहित करना चाहिए ।

16 मानवीय संगठनों की प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता/प्रमाणिकता की कसौटी केवल निर्धारण क्षमता होनी चाहिए ।

17 सभी प्रभावित व्यक्तियों/कुटुम्बों को केंद्रीय आंकड़ों में पंजीकृत होना चाहिए जो राष्ट्रीय प्राधिकरणों, संयुक्त राष्ट्र व अन्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा सहप्रबंधित होने चाहिए ।